



ગુજરાત સરકાર

અસાધારણ અંક ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત

સંખ્યા 155 રાંચી, ગુરુવાર

21 ફાલ્ગુન, 1936 (૬૦)

12 માર્ચ, 2015 (૯૦)

પંચાયતી રાજ એવં એનોઆરોડોપીઓ (વિશેષ પ્રમંડલ) વિભાગ

અધિસૂચના

12 માર્ચ, 2015

સંખ્યા-1 સ્થાન (વિંઠ) - 58/2014...704... -- જીઓ એસ આરો -- ગુજરાત પંચાયત રાજ અધિનિયમ, 2001 (ગુજરાત અધિનિયમ 06, 2001) કી ધારા- 2 કી ઉપધારા (i) દ્વારા પ્રદત્ત શક્તિયોं કા પ્રયોગ કરતે હુએ ગુજરાત કે રાજ્યપાલ ગુજરાત પંચાયત (પિછ્ઢા વર્ગ કે વ્યક્તિયોં કી જનસંખ્યા કા અભિનિશ્ચય એવં પ્રકાશન) નિયમાવલી, 2014 જિસકે પ્રારૂપ કા પ્રકાશન ધારા 131 કી ઉપધારા (1) કે અનુસાર પૂર્વ મેં કિયા જા ચૂકા હૈ, કો પ્રકાશિત કરતી હૈ.

झारखण्ड पंचायत (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन)

नियमावली, 2014

1. संक्षेप नाम एवं प्रारम्भ-

- (i) यह नियमावली झारखण्ड पंचायत (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी.
- (ii) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ – इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001);
- (ख) "धारा" से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा;
- (ग) "जनसंख्या" से अभिप्रेत है ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या, जिसके सुसंगत ऑकड़े प्रकाशित हो गए हैं;
- (घ) "पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा- 2 की उपधारा (i) के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग;
- (ड) "पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा- 2 की उपधारा (i) की अधीन अन्य पिछड़े वर्गों की ऐसी जनसंख्या जिसका अभिनिश्चय अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के ऑकड़ों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार किया गया हो;
- (च) "अभिनिश्चय" से अभिप्रेत है अधिनियम के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ ग्रामवार पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या ज्ञात करने के निमित किया गया कार्य;
- (छ) "ग्राम" से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा-2 की उपधारा (i) के अधीन परिभाषित राजस्व ग्राम;
- (ज) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र;
- (झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली में उपाबद्ध अनुसूची;
- (ज) "विभाग" से अभिप्रेत है पंचायती राज एवं एन० आर० ई० पी०(विशेष प्रमंडल) विभाग;
- (ट) "सरकार/राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड की राज्य सरकार.

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 एवं झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 में उनके लिए दिए गए हैं।

3. पिछङ्गा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय -

- (1) पंचायतों में निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों एवं पदों में पिछङ्गा वर्ग के व्यक्तियों से भरे जाने वाले स्थानों का अनुपात जात करने के लिए अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रकाशित ऑकड़ों के संदर्भ में पिछङ्गा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या अभिनिश्चित की जाएगी;
- (2) उक्त अभिनिश्चय का आधार "बिहार पंचायत (पिछङ्गे वर्गों की व्यक्तियों एवं नागरिकों की संख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 1993" के तहत् ग्रामवार पिछङ्गा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या होगी;
- (3) सर्वप्रथम वर्ष 1991 की जनगणना के ऑकड़ों के तहत् "अन्य" की जनसंख्या में उप नियम (2) के अधीन पिछङ्गा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या का प्रतिशत जात किया जायेगा;
- (4) उप नियम (3) के अधीन पिछङ्गा वर्ग के व्यक्तियों के ज्ञात प्रतिशत को आधार मानकर अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में "अन्य" की जनसंख्या के संदर्भ में पिछङ्गा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या आकलित की जाएगी;
- (5) अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के ऑकड़ों में "अन्य" की जनसंख्या के आधार पर पिछङ्गा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या अभिनिश्चित करते समय गणना में आधा एवं आधा से कम को छोड़ दिया जायेगा तथा आधा से अधिक को एक माना जाएगा ।

4. अभिनिश्चित सूची का प्रकाशन -

- (1) नियम- 3 के अधीन पिछङ्गा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या के आकलन के लिए प्रपत्र-1 में पंजी तैयार की जाएगी;
- (2) नियम- 4 के उप नियम (1) के अधीन प्रपत्र-1 में तैयार पंजी के आधार पर प्रपत्र- 2 में पिछङ्गा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या का प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा;
- (3) प्रपत्र-2 का प्रारूप सम्बन्धित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् कार्यालय में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जायेगा;
- (4) उप नियम (3) के अधीन प्रकाशित प्रारूप में अन्तर्विष्ट किसी बात की सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव, लिखित रूप में, प्रपत्र-2 में प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर

जिला दण्डाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर किसी अन्य पदाधिकारी को दी जा सकेगी;

(5) उप नियम (4) के अधीन आपति या सुझाव प्राप्त होने पर जिला दण्डाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी आवश्यक जाँच के उपरान्त अपना विनिश्चय करेगा जो अंतिम होगा एवं यह विनिश्चय उप नियम (4) में प्रकाशन के निर्धारित अंतिम तिथि से अगले सात दिनों के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा । तत्पश्चात प्रपत्र- 2 में अंतिम रूप से तैयार किया जायेगा ।

5. पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा प्राप्त करना -

(1) जिला दण्डाधिकारी, अभिनिश्चयन कार्य हेतु राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के किसी पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रातिनियुक्त कर सकेगा अथवा इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(2) अभिनिश्चयन का कार्य सही रूप से सम्पन्न हो, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिला दण्डाधिकारी की होगी;

(3) जिला दण्डाधिकारी द्वारा अभिनिश्चयन संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी या उसके समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में प्रातिनियुक्त किया जाएगा, जो यथा निदेशानुसार अपना प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को समर्पित करेगा ।

6. अभिनिश्चित जनसंख्या का प्रकाशन-

(1) नियम 4 के उप नियम (5) के अन्तर्गत प्रपत्र-2 में अंतिम रूप से ग्रामवार अभिनिश्चित पिछ़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या एवं उसकी प्रखण्डवार संकलित संख्या को जिला दण्डाधिकारी अधिसूचना के माध्यम से जिला गजट में प्रकाशित करेगा;

(2) जिला दण्डाधिकारी, प्रकाशित जिला गजट की एक प्रति सरकार के पंचायती राज विभाग एवं राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा;

(3) सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा सभी जिलों से प्राप्त पिछ़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या को जिलावार समेकित कर राजकीय गजट में प्रकाशित किया जायेगा एवं उसकी एक प्रति सभी जिलों एवं राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा ।

7. ऑकड़ों की विमुक्ति एवं सुरक्षा

(1) अभिनिश्चयन कार्य से सम्बन्धित सभी ऑकड़े एवं अभिलेख सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को उपलब्ध एवं विमुक्ति नहीं किए जायेंगे;

(2) अभिनिश्चयन कार्य से सम्बन्धित ऑकड़ो के अभिलेख जिला दण्डाधिकारी की अभिरक्षा में अगले आदेश तक के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे ।

8. कठिनाई दूर करने की व्यवस्था-

झारखण्ड पंचायत राज अभिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत् इस नियमावली के प्रयोजनार्थ पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या के अभिनिश्चय सम्बंधी कार्य में किसी कठिनाई को दूर करने के निमित्त पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य सरकार की सहमति से विधि सम्मत आदेश/निर्देश निर्गत किया जा सकेगा ।

9. व्यावृत्ति-

बिहार पंचायत (पिछड़े वर्गों की व्यक्तियों एवं नागरिकों की संख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 1993 के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत् पूर्व में की गई कारवाई झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की सुसंगत धाराओं के आलोक में अविधिमान्य नहीं समझे जाएंगे मानो उक्त नियमावली उक्त तिथि को प्रवृत्त था जिस तिथि को ऐसी करवाई की गई थी ।

10. शास्ति-

अभिनिश्चयन कार्य में किसी भी स्तर के पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा यदि जानबूझ कर या दुर्भावना से कोई गलती या कर्तव्य की उपेक्षा या लापरवाही किया जाता है तो उसके विरुद्ध झारखण्ड पंचायत राज अभिनियम, 2001 की धारा -131 की उपधारा (3) के तहत् कारवाई की जा सकेगी ।

संचिका संख्या – 1 स्थान (विं) – 58/2014

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

(ह०/-)असपष्ट

प्रधान सचिव

पंचायती राज एवं एन॰आर॰ई॰पी॰

(विशेष प्रमंडल विभाग), झारखण्ड ।

अनुसूची
(नियम- 3 देखिये)
उदाहरण- 1

पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसँख्या अभिनिश्चित करने की प्रक्रिया

प्रथम चरण :

झारखण्ड पंचायत (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसँख्या अभिनिश्चिय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2014 के नियम- 3 के उप नियम (1) में यथा उल्लेख है कि “पंचायतों में निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों एवं पदों में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों से भरे जाने वाले स्थानों का अनुपात ज्ञात करने के लिए अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रकाशित आँकड़ों के सन्दर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसँख्या अभिनिश्चित की जाएगी।” सर्वप्रथम प्रपत्र - 1 के काँलम संख्या 2,3,4,5 एवं 6 में उनसे सम्बंधित व्योरा / आंकड़े अंकित किये जायेंगे। तत्पश्चात नियम 3 के उप नियम (2) के तहत बिहार पंचायत (पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों एवं नागरिकों की संख्या अभिनिश्चिय एवं प्रकाशन) नियमावली, 1993 के आधार पर राजस्व ग्रामवार पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसँख्या को प्रपत्र - 1 के काँलम 8 में अंकित किया जायेगा। नियमावली के नियम 3 के उप नियम (3) के तहत प्रपत्र - 1 के काँलम 9 में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार “अन्य” की जनसँख्या में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात करने हेतु ग्राम की “कुल” जनसँख्या में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या के योग को घटा दिया जायगा और इस प्रकार जो परिणाम प्राप्त होगा वह “अन्य” की जनसँख्या होगी जिसे काँलम 7 में अंकित किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी राजस्व ग्राम-रामपुर (कल्पित नाम) की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसँख्या 2490 है जिसमें अनुसूचित जाति की जनसँख्या 240 तथा अनुसूचित जनजाति की 342 है तो उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार [कुल - (अनुसूचित जाति + अनुसूचित जनजाति) = अन्य] की जनसँख्या प्राप्त की जाएगी। अर्थात् [2490-(240+342)=1908] प्राप्त किया जायगा जिसे प्रपत्र - 1 के काँलम 7 में अंकित किया जायेगा।

अब चुंकि झारखण्ड पंचायत (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसँख्या का अभिनिश्चिय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप नियम (3) के तहत पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसँख्या का प्रतिशत “अन्य” की जनसँख्या (1908) में से प्राप्त करना है, तो इसके लिए निम्नवत गणना की जायेगी-

1. वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम रामपुर की “कुल” जनसँख्या – 2490
2. वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम रामपुर में “अन्य” की जनसँख्या – 1908
3. वर्ष 1993 की नियमावली के अनुसार पिछड़ा वर्ग की व्यक्तियों की अभिनिश्चित कुल जनसँख्या – 490

4. वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम रामपुर की - $\frac{490 \times 100}{1908} = 25.68$
 अन्य की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग की व्यक्तियों का प्रतिशत : 1908
 प्राप्त प्रतिशत को प्रपत्र -1 के कॉलम 9 में अंकित किया जायेगा ।

द्वितीय चरण :

इस चरण में प्रपत्र - 1 के कॉलम 10,11 एवं 12 से सम्बंधित कार्य किये जायेंगे । इस निमित नियम-3 के उप नियम (4) के अधीन यथा उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, 2011 (यदि वर्ष 2011 की जनगणना के सन्दर्भ में आँकड़े प्राप्त करना हो तो) की “कुल” जनसंख्या में से “अन्य” की जनसंख्या प्राप्त की जायेगी तथा प्रपत्र - 1 के कॉलम 10 में उक्त आँकड़ों को अंकित किया जायेगा । उदाहरणस्वरूप, यदि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम रामपुर की “कुल” जनसंख्या 2692 है जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 292 तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 398 है तो “अन्य” की जनसंख्या जात करने के लिए उक्त ग्राम की “कुल” जनसंख्या में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के योग को घटा देने से ‘अन्य’ की जनसंख्या प्राप्त हो जायेगी, अर्थात् $2692 - (292 + 398) = 2002$ होगा ।

तत्पश्चात प्रथम चरण के क्रमांक 4 में प्राप्त पिछड़े वर्ग में व्यक्तियों की जनसंख्या के प्रतिशत को अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना (2011) के ‘अन्य’ की जनसंख्या के सन्दर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या निम्नवत आकलित की जायेगी –

1. अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना (2011) के अनुसार ग्राम रामपुर की ‘कुल’ जनसंख्या-	2692
2. अनुसूचित जाति की जनसंख्या -	292
3. अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या-	398
4. ‘अन्य’ की जनसंख्या :	$2692 - (292 + 396) = 2002$

पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या - द्वितीय चरण के क्रमांक	\times	प्रथम चरण के क्रमांक
4 से प्राप्त आँकड़ा		4 से प्राप्त प्रतिशत
	100	
अर्थात्	$\frac{2002 \times 25.68}{100}$	= 514.11
	100	

उपर्युक्त आँकड़ों को प्रपत्र - 1 के कॉलम 11 में अंकित किया जायेगा ।

झारखण्ड पंचायत (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चिय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप नियम (5) के अधीन अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना (2011) के आँकड़ों के सन्दर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या को अभिनिश्चित करते समय गणना में आधा एवं आधा से कम छोड़ देना है तथा आधा से अधिक को एक माना जाना है । इसलिए उपर्युक्त प्रकार से आकलित पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या जो 514.11 प्राप्त हुआ है उसे नियम 3 के उप नियम (5) के अधीन रहते हुए 514 माना जायगा तथा प्रपत्र - 1 के कॉलम 12 में तदनुसार अंकित किया जायेगा ।

प्रपत्र - 1

(नियम- 4 (1) देखिये)

पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय पंजी

जिला

जिला दंडाधिकारी द्वारा प्राधिकृत

पदाधिकारी का नाम, हस्ताक्षर व मुहर

प्रारूप

अंतिम

प्रपत्र - 2

(नियम - 4 देखिये)

ज़िला

प्रखण्ड.....

क्र०सं०	ग्राम का नाम	थाना संख्या	पिछङ्गा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्वत जनसंख्या
1	2	3	4

ज़िला दंडाधिकारी

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 155—50+500 |